

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 14 जनवरी, 2021 को सायं 05.00 बजे विडियो कॉन्फ्रैंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार सदस्य
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली सदस्य
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSCA)

बैठक का आरंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के औपचारिक स्वागत से हुआ। समिति के सदस्यों ने माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के समक्ष अपना परिचय दिया और समय-2 पर उच्चाधिकार समिति के सुझावों और सिफारिशों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं और उनसे संबंधित भूमिकाओं के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को जानकारी दी।

एजेंडा: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020– In Re: Contagion of COVID-19** दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020 में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1: पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार पर कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया और माननीय अध्यक्ष को समिति की पहले की बैठकों में लिए गए निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के विषय में विस्तृत रूप से अवगत करवाया। उन्होंने आगे सूचित किया कि पहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे कोविड-19 के मामलों की वृद्धि के ऊपर जांच रखने में सफल रहे हैं और वे जेल परिसर के अंदर कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रिय केसों की संख्या को भी कम करने में भी सफल रहे हैं।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उनके पत्र संख्या **PS/DG(P)/2020/ 17-22** दिनांक 04.01.2021 के द्वारा दिनांक 04.01..2021 तक दिल्ली जेल में कोविड-19 के पाजिटिव केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार है:

जेल में बंद कैदियों के मामले : 115 (113ठीक हुए, 02की मृत्यु, 0सक्रिय मामले)

जेल स्टॉफ : 290 (288 ठीक हुए, 02 सक्रिय मामले)

हालांकि महानिदेशक (जेल) बैठक के दौरान समिति के संज्ञान में लाए कि मंडोली की जेल नं. 13 के एक कैदी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने से पूर्व उसका कोविड-19 टेस्ट करवाया गया था और वो पाजिटिव पाया गया। उन्होने आगे सूचित किया कि उसकी contact tracing कर ली गई है और उसकी बैरेक के 26 अन्य कैदियों का "रेपिड एंटीजन टेस्ट" कर लिया गया है। इस टेस्ट के दौरान एक अन्य कैदी भी कोविड-19 पाजिटिव पाया गया। इन दोनों कैदियों को अलग से एकांत में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि वे शीघ्र ही इन कैदियों का RTPCR टेस्ट करवाए और तब तक उन्हें जेल के अन्य कैदियों से धुलने मिलने की आज्ञा न दी जाए। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 20.06.2020 तथा उसके बाद की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन 55 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे प्रतिरक्षा में अक्षम न हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने उन सभी संभावित तरीकों के विषय में विचार विमर्श किया जिससे कि कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) जेल परिसर में प्रवेश कर सकता है। कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया जो कि:

- (ए) नए प्रवेशक जिसमें अंतर्रिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले समिलित हैं।
- (बी) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ
- (सी) राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्ति।

जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर **रैपिड टेस्ट** कर रहे हैं। उन्होंने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उन्होंने आगे सूचित किया कि उन्होंने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करने के साथ –2 कैदियों से बात करते समय **पीपीई किट**, मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि अध्यक्ष के द्वारा दिए गए को सुझाव के अनुसार स्टॉफ दो परत सुरक्षा मास्क का प्रयोग कर रहा है और मास्क के साथ –2 वे वाइसर (visor) का भी नियमित रूप से प्रयोग भी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे सूचित किया कि दिनांक 04.01.2021 तक **290** जेल स्टॉफ कोविड पॉजिटिव पाया गये थे। जिसमें से **288** पहले ही ठीक हो चुके हैं। उन्होंने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल **02** सक्रिय केस हैं जो कि घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड-19** पॉजिटिव पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जा रही है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट किया जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होंने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे कि जेल परिसर के अंदर **कोविड-19** के प्रसार को रोका जा सके।

नए प्रवेशकों जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले सम्मिलित हैं, के लिए उठाए गए एहतियाती उपाय

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि नए प्रवेशकों को अलगाव वार्ड में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से घुलने मिलने से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न. 7 और जेल न. 8/9 मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल (संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को “अलगाव वार्ड” के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरुष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की

आयुवाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में “अलगाव वार्ड” के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि “अलगाव वार्ड” अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को अस्थाई जेल के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के नए प्रवेशकों को रखने के लिए अलगाव वार्ड के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जा सके।

अस्थायी जेल : जेल में अतिरिक्त आवास

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने अस्थायी जेल बनाने और उसे अलगाव वार्ड के रूप में प्रयोग करने के लिएराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से 12 टावरके आबंटन के लिए पुख्ता प्रयासकिएहैं जिसमें प्रत्येक टावर में 30 फ्लैट हैं।

प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्लीकी अधिसूचना न. **9/70/2020/HG/2427-2441** दिनांक **31.07.2020**के द्वारा कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थितपुलिस क्वार्टरों को अस्थायी जेल घोषित कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित कियाकि पुलिस आवासीय परिसर, मंडोली में 12 टावर हैं जिसमें से प्रत्येक में 30 फ्लैट हैं। उन्हें अस्थायी जेलों के रूप में प्रयोग करने के संबंध में आज महानिदेशक (जेल) ने बताया कि 12 टावरों में से अब 6 टावर बी, सी, डी, ई आई, और जे ब्लॉक पूरी तरह अस्थायी जेलों के रूप में से क्रियाशील हैं। यह भी बताया गया कि वर्तमान में इन टावरों में उन्होने 340 कैदियों को रखा है जिसे उन्होने अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया है। उन्होने आगे यह भी बताया कि टावर जी, एच जे, के एवं एलटावर कैदियों को रखने के लिए तैयार है और उन्हें भी शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जाएगा। उन्होने बताया दो टावर ए और एफ को बाहरी सुरक्षा बलों को रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है। जिससे कि वे जेल स्टॉफ के साथ घुलना मिलना कम किया जा सके।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि वर्तमान में अस्थायी जेलों में कैदियों को रखा गया है और अन्य को आत्मसमर्पण के पश्चात रखा जाएगा। अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा किए गए उनके सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अध्यक्ष की अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा की चिंता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने “अस्थायी जेल” में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों के विषय में अध्यक्ष को अवगत करवाया।

उन्होंने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां “अस्थायी जेल” में रखी गई हैं। उन्होंने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को सील करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैट्स/अपार्टमेन्ट की बालकनी को सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की समावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाए तो अस्थायी जेल के इन टावरों में लगभग 2000 कैदियों को रख सकते हैं। महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए अलगाव वार्ड बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो गई है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया किया कि वे सभी विचाराधीन कैदी/दोषी न्यायालयद्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए दिल्ली की जेलों में आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरुष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में क्रमशः अलग अलगाववार्ड में रखा जाएगा।

जेल अस्पताल

अध्यक्ष ने जेल अस्पताल में आक्सीजन से संबंधित मशीनों के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के रेपिड एंटीजन टेस्ट संबंधमें पूछताछ की। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होंने आक्सीजन से संबंधित 04 मशीने खरीदी थी उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने आक्सीजन से संबंधित 15 मशीनों की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन से संबंधित मशीने उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के रेपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में आक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ–2 आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है।

अन्य एहतियाती उपाय

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं और सामाजिक दूरी के सिद्धांत का गहनतापूर्वक पालन कर रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जेलों में स्थापित “पब्लिक एड्सेस सिस्टम” के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें “क्या करना चाहिए क्या नहीं”।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड-19 (नोवेल करोना वायरस)** के लक्षण पाते हैं या किसी पर संदेह करते हैं तो उसे ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होंने **कोविड-19 (कोरोना वायरस)** के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसे:

- (ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के दौरा करने पर रोक।
- (बी) कैदियों के वार्ड से बाहर घूमने फिरने पर रोक।
- (सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित रखना।
- (डी) सभी नए कैदियों को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में पूर्व जांच की जाती है।
- (ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की खरीद और वितरण।
- (एफ) सभी जेलों में संदिग्ध कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के **“Contact Tracing”** के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन।

(जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।

(एच) रसोई/कैटीन में कर्मियों द्वारा रसोई की स्वच्छता और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग पर बल।

महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम न. 2: जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से कोविड-19 (कोरोना वायरस) कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होंने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होंने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ के लिए रेपिड टेस्ट का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल स्टॉफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आगाह किया गया है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। तदानुसार यह हल किया जाता है।

आइटम नंबर 3: जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैच के द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020, 05.05.2020, 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020 और 28.11.2020 को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का व्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों के अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार परव्यक्तिगत बांड पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया। महानिदेशक (जेल) के पत्रांक **PS/ DG(P)/2021/2072-73** दिनांक 09.01.2021 में आंकड़े भी वर्णित हैं।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक 09.01.2021 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	3499
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	310
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	1184
दिनांक 09.01.2021 तक सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	130
दिनांक 09.01.2021 तक अंतरिम जमानत/पैरोल/सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी जो कि माननीय उच्चाधिकार समिति के तत्वाधान में भीड़ कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ही रूप है।	5123

अंतरिम जमानत:

समिति के सदस्यों ने स्वयं को उस लक्ष्य का स्मरण करवाया जिसको ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस शीर्षक **"Suo Motu Petition (Civil) No.1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19"** के द्वारा समिति का गठन उन कैदियों के श्रेणी/वर्ग पर विचार करने के लिए किया था जिनको अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर नहीं बल्कि अपराध की प्रकृति और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समिति का गठन, महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितयों जिसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन और न्यायालय के कार्य प्रतिबंधित हो गए थे, के कारण किया गया था। जिससे कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। समिति के सदस्यों ने दिनांक 13.04.2020 के बाद के आदेश का स्मरण कराया जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने राज्यों को कैदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का आदेश नहीं दिया है।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह महसूस किया कि इस समिति का गठन उपरोक्त लक्ष्य को लेकर किया गया था जिसका उद्देश्य केवल जेलों की भीड़ को कम करने का हल ढूँढ़ना और वायरस के प्रसार से बचना था और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि इन परिस्थितियों में अंतरिम जमानत से लाभ सामाजिक गिरावट के लिए नहीं हो सकता है।

समिति के सदस्यों की यह रूँय है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी आधार पर की गई है और इसका अर्थ कभी भी जमानत के या मान्यता प्राप्त सिद्धांतों/अनुदानों से इनकार के पूरक के रूप में नहीं था। इसके अतिरिक्त ये उपाय तब किए गए जब लॉकडाउन और मौजूदा परिस्थितियों के कारण न्यायालयों का कामकाज प्रतिबंधित था। हालाँकि स्थिति अब बदल गई है, इसलिए इन अस्थायी उपायों को सदा के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है।

भारत सरकार के दिनांक 30.09.2020 के आदेश सं. **40-3/2020-DM-I(A)** को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 5 के संबंध में है और जो दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी है और तदानुसार परिस्थितियों के परिवर्तन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं. **538/RG/DHC/2020** दिनांक 19.10.2020 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी न्यायालय जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कार्य पुनः भौतिक रूप/विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुरू हो रहे हैं। इस समिति ने यह निर्णय लिया है कि कि विचाराधीन कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की सिफारिशों के मानदंडों को और अधिक लचीला नहीं बनाया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के लाभ जो कि पिछली बैठक के अनुसार दिनांक 30.09.2020 तक जारी रहना था, को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

समिति के सदस्यों का यही विचार है कि सभी न्यायालय यानि माननीय उच्च न्यायालय के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं अतः सभी विचाराधीन कैदी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आवेदन जब कभी भी दायर किए जाएंगे तो कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

हालांकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है परंतु फिर दोहराया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.4.2020, 05.05.2020, 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020, 24.10.2020 एवं 28.11.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में नहीं आते हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकते हैं। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकते हैं।

सजा की छूट :

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि**दिनांक 28.03.2020** की उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने आदेश सं. F.9/63/2020 दिनांक 07.04.2020 के द्वारा पात्र दोषियों को सजा की छूट प्रदान की है। उन्होंने आगे सूचित किया कि कार्यालय आदेश के अनुसार आज तक **72** दोषियों को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं. F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश दिया गया है। जो कि **30 सितम्बर, 2020** तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस नए आदेश के आधार पर आज तक **33** और दोषियों को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः आज तक **105** दोषियों को सजा की छूट का लाभ मिला है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि पुनः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने दिनांक 07.04.2020 के सजा की छूट आदेश को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया है। तदानुसार **25** अन्य दोषी रिहा हो गए हैं। दिनांक 09.01.2021 तक **130** दोषियों को सजा की छूट का लाभ मिला है।

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की सराहना की।

आइटम नंबर 4:-दिनांक 30.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक **28.11.2020** की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होंने दिनांक **30.11.2020** को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number 3080/2020***, titled "***Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr.***" दिनांक 02.12.2020 के आदेश में जिन 3499 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानतको आगे बढ़ा दिया गया था उनकी अंतरिम जमानतको उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से 45 दिनों के लिएआगे बढ़ा दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए जाने के साथ -2 समिति के दिनांक 28.11.2020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों (जिसमें 3499 विचाराधीन कैदी सम्मिलित हैं) को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की अवधि 20.01.2021 से समाप्त होने जा रही है।

महानिदेशक (जेल) समिति के संज्ञान में लाए कि यदि इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन 3499 विचाराधीन कैदियों और 1184 दोषियों को अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल दी गई है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है तो दिल्ली की जेलों की कुल आबादी 21,500 तक पहुँचने की संभावना है जो कि अभूतपूर्व होगी और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के कारण असहनीय हो सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि आज तक केवल एक अवसर पर दिल्ली की जेलों की अधिकतम आबादी 18,000 तक पहुंची है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दिनांक 08.01.2021 के आदेश से 1184 दोषियों की आपातकालीन पैरोल की अवधि चार सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई है जो कि अब दिनांक 07.02.2021 से समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह उचित होगा यदि आपातकालीन पैरोल प्रदान किए गए दोषियों को अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों से पूर्व आत्मसमर्पण के लिए कहा जाए।

महानिदेशक (जेल) ने आगे कहा कि वर्तमान जेल जनसंख्या जो कि 16,396 (दिनांक 12.01.2021 तक) है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह उचित होगा कि उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत 3499 विचाराधीन कैदियों को प्रदान की गई अंतरिम जमानत को 30 दिनों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।

महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 14.01.2021 का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 14.01.2021 का पत्र को पढ़ा और महानिदेशक (जेल) द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार विमर्श किया। समिति के सदस्यों ने दिल्ली जेलों की कुल क्षमता पर भी विचार किया जो कि इस प्रकार है:

क्रम सं.	जेल परिसर	कैदियों की संख्या
1.	तिहाड़	5200
2.	रोहिणी	1050
3	मंडोली	3776
	कुल	10026

समिति के सदस्यों ने विचार किया कि आज तक इसकी क्षमता के विरुद्ध वहां पहले से ही **16396** कैदी हैं और यहां तक कि यदि 2000 कैदियों के लिए नई बनायी गई अस्थायी जेल के अतिरिक्त आवास पर भी विचार किया जाए तो इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के तहत अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल पर रिहा विचाराधीन कैदियों/दोषियों को समायोजित करना जेल प्राधिकारियों के लिए अत्यंत असुविधाजनक होगा यदि वे एक साथ आत्मसमर्पण करेंगे।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जो अभी आपातकालीन पैरोल की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें उनकी आत्मसमर्पण की तिथि से 14 दिनों की अवधि के लिए अलगाव वार्ड में रखा जाएगा। अतः समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा दिए गए तर्कों को उचित पाया कि 3499 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को 30 दिनों की अवधि को आगे बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है।

समिति केसदस्यों की यह राय है कि जेल प्राधिकारियों को किसी प्रकार की अराजकता और असुविधा को रोकना उचित होगा। यदि समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंडों के आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदियों को फरवरी, 2021 को आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है तो उस समय तक आपातकालीन पैरोल की अवधि के समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने वाले दोषियों को एकांत में रखने की अवधि समाप्त हो जाएगी।

इन सभी संबंधित कारकों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अर्थात :

- (ए) दिल्ली जेल की वास्तविक धारण क्षमता।
- (बी) वर्तमान अधिभोग।
- (सी) माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के द्वारा पारित दिनांक

20.10.2020 के आदेशानुसार दिनांक **02.11.2020** से **13.11.2020** तक आत्मसमर्पण करने वाले विचाराधीन कैदियों / दोषियों की संख्या।

- (डी) उन्हें नियमित जेल भेजने से पूर्व उन्हें 14 दिन अलगाव वार्ड में रखने की अवधि।

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार सिफारिश की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये 3499 विचाराधीन कैदी जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आते हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी निजी अधिवक्ता अथवा डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन सिफारिशों को इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की 30 दिन की अवधि के लिए सूचित करेगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचाराधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

हालांकि यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस समिति द्वारा अलग-2 न्यायालयों द्वारा अलग-2 तारीखों में 45 दिनकी अवधि के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत की यह अवधि इस समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बैच द्वारा **"W.P.(C) 3080/2020"** शीर्षक **"Court on its own Motion Vs.State"**, आरंभ मेंदिनांक 09.05.2020 के आदेश द्वारा, जिस तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही थी, उस तारीख से 45 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी और उसी को समय-2 पर दिनांक 22.06.2020, 04.08.2020, 18.09.2020 और अंत में 02.12.2020 को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इन 3499 विचाराधीन कैदियों को अलग-2 तारीखों पर अंतरिम जमानत दी गई थी। इस तरह उनकी अंतरिम जमानत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी इसलिए उनके आत्मसमर्पण के लिए अलग से तारीखों की आवश्यकता नहीं है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति समान रहती है या इसमें गिरावट का पता चलता है तो समिति द्वारा कोविड-19 के संबंध में अंतरित जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे सभी विचाराधीन कैदी अपने निजी वकील या डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा भी मामला हो, और ऐसे

सभी न्यायालय जमानत याचिका पर मेरिट के अनुसार विचार करेंगे। इस समिति के द्वारा अभिलिखित मानदंड इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

आइटम नंबर 5:- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे 4 सप्ताह के लिए बढ़ाने के संबंध में फीडबैक

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने दोषियों को 8 सप्ताह के लिए आपातकालीन पैरोलप्रदान की थी। जो कि बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई।

समिति ने इसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए और पहले दिल्ली में महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए उस समय महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को पहले से ही प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से अपेक्षित अनुरोध निर्देश दिया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के F.No.18/191/2015-HG/3823-29 दिनांक 03.12.2020 के आदेश से उन सभी दोषियों की जिनकी आपातकालीन पैरोल की अवधि दिनांक 09.01.2021 को या उससे पूर्व समाप्त होने जा रही थी, उसको 6 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

1184 दोषियों की आपातकालीन पैरोल की अवधि को आगे बढ़ाने के संबंध में महानिदेशक (जेल) द्वारा विशेष सचिव (गृह) को पत्रांक F. 10 (003598848)/CJ/LEGAL/PHQ/ 2020/ 506 दिनांक 04.01.2021 को पत्र लिखा गया था जिसे वे समिति के संज्ञान में लाए।

महानिदेशक (जेल) ने कहा कि जेल की जनसंख्या पर विचार करते हुए उक्त पत्र लिखा था जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जेल के अंदर भीड़भाड़ न हो जाए। प्रधान सचिव (गृह) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के दिनांक 08.01.2021 के आदेश से 1184 दोषियों की आपातकालीन पैरोल की अवधि 4 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

इस पर विचार करने के पश्चात समिति की रॉय है कि वर्तमान में 1184 दोषियों की आपातकालीन पैरोल की अवधि 4 सप्ताह के लिए पहले ही आगे बढ़ा दी गई है। अतः इस संबंध में समिति को कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि से सिफारिशों दिल्ली में **कोविड-19** की स्थिति पर विचार करते हुए की गई थी। समिति के सदस्यों ने कहा कि यदि दिल्ली में **कोविड-19** की स्थिति समान रही या उसमें गिरावट दर्ज की गई तो **कोविड-19** के आधारपर दोषियों की आपातकालीन पैरोल को आगे बढ़ाने की सिफारिश नहीं की जाएगी।

बैठक के कार्यवृत्त का पालन सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल
महानिदेशक (जेल)

श्री एस.एस. भल्ला
प्रधान सचिव (गृह)

कंवलजीत अरोड़ा
सदस्य सचिव
डीएसएलएसए

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांगी,
कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता है कि दिनांक 14.01.2021 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक
डीएसएलएसए